ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

कल्याण बनर्जी

(2008 सिविल अपील सं. 1736)

मार्च 4,2008

[एस. बी. सिन्हा एवं वी. एस. सिरपुरकर, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950:

अनुच्छेद 226(2) - प्रादेशिक क्षेत्राधिकार - झारखंड राज्य में मुगमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली कार्रवाई का वाद हेतुक - कर्मचारी द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध रिट याचिका - की संधार्यता - अभिनिर्धारित - असंधार्य- कंपनी का पश्चिम बंगाल राज्य में प्रधान कार्यालय कलकत्ता में होने मात्र से कलकत्ता उच्च न्यायालय को प्रादेशिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रधान कार्यालय का कर्मचारी के खिलाफ सजा के आदेश से कोई लेना-देना नहीं है।

शब्द और वाक्यांश: वाद हेतुक - अर्थ - भारत के संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226(2) के संदर्भ में।

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर कंपनी का प्रधान

कार्यालय स्थित था, के पास उस कर्मचारी के रिट आवेदन पर विचार करने का क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है, जिसमें कर्मचारी को कंपनी में नियुक्त किए जाने पर उसकी बर्खास्तगी को चुनौती दी गई थी। झारखंड में मुगमा क्षेत्र में और उस स्थान पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट या मेंडमस की प्रकृति जारी करने का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय जी को प्रदान किया गया है। हालाँकि, अनुच्छेद 226(2) में यह प्रावधान है कि यदि वाद हेतुक एक से अधिक अदालतों में उत्पन्न हुआ है, तो किसी भी अदालत में जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है, उसे रिट याचिका पर विचार करने का क्षेत्राधिकारी होगा। (पैरा 6) [924-एफ, जी]

1.2 'वाद हेतुक', भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के प्रयोजन के लिए, सभी आशय और आशय के लिए, धारा 20(सी) सीपीसी के तहत परिकल्पित के समान अर्थ दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है तथ्यों का एक बंडल जिसे साबित करना आवश्यक है। हालाँकि, प्रस्तुत किए गए तथ्यों के पूरे समूह को कार्रवाई का कारण बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो साबित करना आवश्यक है वह भौतिक तथ्य हैं जिसके आधार पर एक रिट याचिका की अनुमति दी जा सकती है। (पैरा 7) [924-जी, एच; 925-ए]

1.3 कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर कार्रवाई का वाद हेतुक झारखंड राज्य के भीतर मुगमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, यह राय है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता- कंपनी का मुख्य कार्यालय राज्य में स्थित था। पश्चिम बंगाल का, यह अपने आप में कलकत्ता उच्च न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा, खासकर जब प्रधान कार्यालय का प्रतिवादी के खिलाफ पारित सजा के आदेश से कोई लेना-देना नहीं था। (पैरा 11) [928-सी, डी]

कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य (2004) 6 एससीसी 254; नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण एआईआर 1976 एससी 331; ऊपर। राष्ट्रीय चीनी मिल अधिकारी परिषद, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य (1995) 4 एससीसी 738; मोसराफ हुसैन खान बनाम भागीरथ इंजीनियरिंग। लिमिटेड और अन्य (2006) 3 एससीसी 658; ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य (2006) 6 एससीसी 207; उत्तरांचल वन रेंजर्स एसो. (सीधी भर्ती) और अन्य बनाम यूपी राज्य। और अन्य (2006) 10 एससीसी 346 - संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 1736

आर.वी.डब्ल्यू. क्रमांक 1709/2003 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 25/11/2005 के निर्णय और अंतिम आदेश से। डब्ल्यू.पी. में क्रमांक 19934 (डब्ल्यू) /1999.

अपीलकर्ताओं की ओर से - अनिप सचथे।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. प्रतिवादी झारखंड के धनबाद जिले में मुग्मा क्षेत्र में अपीलकर्ता नंबर 1, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का कर्मचारी था। क्षेत्र के महाप्रबंधक, जिनका कार्यालय मुगमा में भी स्थित है, उनकी नियुक्ति और अनुशासनात्मक प्राधिकारी थे। मुग्मा में प्रतिवादी की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट आवेदन दायर किया। चूंकि वह मुगमा क्षेत्र में कार्यरत थे और महाप्रबंधक का कार्यालय मुगमा में स्थित था जो झारखंड राज्य में है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी। उक्त आपत्ति के समर्थन में एकल विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत, एन.एन. सिंह बनाम कोल इंडिया लिमिटेड [सी.ओ. क्रमांक 5869 (डब्ल्यू) 1994] के निर्णय पर निर्भर किया गया।

3. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त दृष्टिकोण से असहमति जताई और मामले को डिवीजन बेंच को भेज दिया। डिवीजन बेंच ने 26.03.2003 के एक निर्णय और आदेश द्वारा राय दी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय उक्त रिट याचिका पर विचार करने का कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था।

> "...इस मामले में डिवीजन बेंच द्वारा एक टिप्पणी पर भरोसा करते हुये यह अभिनिर्धारित किया गया।
>
> विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि पंजीकृत होने के बाद से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्यालय सैंकटोरिया में स्थित है,
>
> इस न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में बर्दवान, जो एक आवश्यक पक्ष है और बर्खास्तगी के अनुमोदन का आदेश भी अंततः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक, कार्मिक से प्राप्त किया गया था, जिसका कार्यालय उक्त पंजीकृत कार्यालय में है, रिट याचिका कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष रखी जा सकती है। इसलिए, यह मामला अनिवार्य रूप से तथ्यों पर तय किया गया था, लेकिन याचिका में ऐसा कोई कथन नहीं है कि महाप्रबंधक, बदीना कोलियरी, मुगमा क्षेत्र, धारबाद द्वारा पारित समाप्ति के आदेश पारित

करने से पूर्व प्रधान कार्यालय कलकत्ता से अनुमोदन प्राप्त किया था।

अतः इस न्यायालय के डिविजन बेंच का निर्णय हस्तगत प्रकरण के रिट याचक / रिसपोंडेंट पर लागू नहीं होता है।

उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों के अनुसार, मामले का निर्णय करने के लिए क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्राप्त करने के लिए वाद हेतुक मामले का निर्णायक है। सिर्फ इसलिए कि कंपनी का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में है, इस मामले में निर्णायक नहीं है। जैसा कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बनाम उत्पल कुमार बसु (सुप्रा) के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि क्योंकि इससे पार्टी को कार्रवाई का वाद हेतुक नहीं मिलेगा। वाद हेतुक, तथ्यों का एक समूह है जो न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार का फैसला करता है, यदि कार्रवाई का वाद हेतुक कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर पार्टी के लिए उत्पन्न हुआ है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास मामले का फैसला करने का क्षेत्राधिकार होगा। केवल इसलिए कि कंपनी का मुख्य कार्यालय कलकत्ता उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर है, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय को अधिकार क्षेत्र

नहीं देगा, जब तक कि कार्रवाई का वाद हेतुक कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न न हो।"

4. इसके पश्चात् एक पुनर्विलोकन आवेदन दायर किया गया था। दिनांक 25.11.2005 के आक्षेपित निर्णय के कारण, उक्त पुनर्विलोकन आवेदन को यह कहते हुए अनुमति दी गई है कि डिवीजन बेंच ने उक्त न्यायालय की डिवीजन बेंच के दो अन्य निर्णयों, जैसे राम ब्रिच मुची बनाम कोल इंडिया, पर विचार नहीं किया था। लिमिटेड [ए.पी.ओ.टी. 2002 की संख्या 343] और ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बनाम खगेन बाउरी और अन्य। [2002 (1) सी.एल.आर. 884]। इसके अलावा यह राय दी गई:

"जैसा कि कंपनी अधिनियम में प्रावधान है, एक कंपनी एक कॉर्पोरेट निकाय है और उसके पंजीकृत कार्यालय को सभी मुकदमों के लिए उसकी साइट माना जाना चाहिए। कानून समान रूप से स्थापित है कि बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाले कर्मचारी को प्रभावी आदेश नहीं मिल सकता है जब तक नियोक्ता को मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जाता है और इस तरह, इस मामले में, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय बर्दवान जिले में है, एक आवश्यक पक्ष है और यदि न्यायालय रिट

याचिकाकर्ता को राहत देने का प्रस्ताव करता है, तो विशिष्ट निर्देश बहाली का अधिकार नियोक्ता को उसके उपयुक्त अधिकारियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(1) में प्रदान किया गया है। यदि वाद हेतुक उच्च न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के बाहर उत्पन्न होता है, तो ऐसा उच्च न्यायालय एक रिट आवेदन पर विचार तभी कर सकता है जब न्यायालय के आदेश से बाध्य होने वाला व्यक्ति क्षेत्रीय सीमा के भीतर तैनात है। अनुच्छेद 226(2) एक अतिरिक्त प्रावधान है। जिसे बाद में संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है जो उच्च न्यायालय को उन मामलों में भी रिट जारी करने में सक्षम बनाता है। जहां उत्तरदाता अपनी क्षेत्रीय सीमा से परे कार्य कर रहे हैं। यदि वाद हेतुक पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसकी क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है।

एक बार जब यह मान लिया जाता है कि अनुच्छेद 226(1) स्पष्ट रूप से लागू है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुर्नविलोकन किए जाने वाले आदेश से, हम पाते हैं कि

डिवीजन बेंच ने अपना ध्यान वर्तमान रिट आवेदन की कार्रवाई के कारण तक ही सीमित रखा, लेकिन इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि नियोक्ता, सरकारी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बर्दवान जिले के भीतर है और परिणामस्वरूप यह प्रश्न कि क्या वाद हेतुक वास्तव में इस न्यायालय की क्षेत्रीय सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ था, सारहीन था।"

5. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अनिप सचथे ने प्रस्तुत किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां कॉर्पोरेट कार्यालय या प्रधान कार्यालय की मंजूरी लेने की आवश्यकता है। संपूर्ण वाद हेतुक झारखंड उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पन्न होने के कारण, कलकत्ता उच्च न्यायालय इस मामले में किसी भी क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था।

6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट या मेंडमस की प्रकृति जारी करने का अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। हालाँकि, अनुच्छेद 226(2) में यह प्रावधान है कि यदि वाद हेतुक एक से अधिक अदालतों में उत्पन्न हुआ है, तो किसी भी अदालत में जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है, उसे रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्राधिकार होगा।

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226(2) के प्रयोजन के लिए, 'वाद हेतुक', सभी आशय और अभिप्राय के लिए, वही अर्थ दिया जाना चाहिए जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 20 (सी) एच के तहत परिकल्पित है। इसका अर्थ है तथ्यों का एक समूह जो सिद्ध करना आवश्यक है। हालांकि अनुरोध किये गये संपुर्ण तथ्यों के बंडल का एक वाद हेतुक होना आवश्यकता नहीं है ठीक वैसे ही क्याेंकि भौतिक तथ्यों को साबित करना आवश्यक है जिसके आधार पर रिट याचिका की अनुमति दी जा सकती है।

इस प्रश्न पर कुछ हद तक कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य [(2004) 6 एससीसी 254] में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार किया गया था। जो कि निम्न प्रकार है-

> "18. रिट याचिका में दिए गए तथ्यों में उस आधार पर संबंध होना चाहिए जिसके आधार पर प्रार्थना स्वीकार की जा सके। जिन तथ्यों का उसमें की गई प्रार्थना से कोई लेना-देना नहीं है, उन्हें वाद हेतुक बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो न्यायालय पर क्षेत्राधिकार प्रदान करेगा।"

इस प्रश्न के संबंध में कि क्या अपीलकर्ता के पद की स्थिति प्रासंगिक होगी, इस न्यायालय ने नसीरुद्दीन बनाम राज्य परिवहन अपीलीय

न्यायाधिकरण [एआईआर 1976 एससी 331] और यू.पी. में इस न्यायालय के निर्णयों पर ध्यान दिया। राष्ट्रीय चीनी मिल अधिकारी परिषद, लखनऊ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। और अन्य [(1995) 4 एससीसी 738] अभिनिर्धारित :-

> "26. यूपी राष्ट्रीय चीनी मिल अधिकारी परिषद में इस न्यायालय का दृष्टिकोण है कि सरकार द्वारा आदेश या अधिसूचना जारी करने की स्थिति (समामेलन) के खंड 14 में "उत्पन्न होने वाले मामले" अभिव्यक्ति के अर्थ में आएगी। इसके बाद बताए गए कारण से आदेश कानून का सही दृष्टिकोण नहीं है और उस हद तक उक्त निर्णय को खारिज कर दिया जाता है। वास्तव में, एक कानून, यह तुच्छ है, संसद या किसी राज्य की विधायिका द्वारा अधिनियमित क़ानून तक ही सीमित नहीं है, जो इसमें प्रत्यायोजित कानून और अधीनस्थ कानून या भारत संघ, राज्य या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कार्यकारी आदेश शामिल होगा। ऐसे मामले में जहां क्षेत्र किसी वैधानिक नियम के अंतर्गत नहीं आता है, इस संबंध में जारी कार्यकारी निर्देश भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसका दायरा। संसद, राज्य की विधानमंडल या अधीनस्थ कानून

बनाने के लिए सशक्त प्राधिकारियों के कार्यालय की स्थिति स्वयं कार्रवाई या उत्पन्न होने वाले मामलों का कोई कारण नहीं बनेगी। दूसरे शब्दों में, किसी क़ानून, वैधानिक नियम को तैयार करना या कार्यकारी आदेश या निर्देश जारी करना केवल उसके निर्माता के पद की स्थिति के कारण किसी अदालत को क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा।

27. हालाँकि, जब कोई आदेश किसी अदालत या न्यायाधिकरण या कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, चाहे वह किसी क़ानून के प्रावधानों के तहत हो या अन्यथा, उस स्थान पर कार्रवाई का एक कारण उत्पन्न होता है। किसी दिए गए मामले में भी, जब मूल प्राधिकारी का गठन एक स्थान पर किया जाता है और अपीलीय प्राधिकारी का गठन दूसरे स्थान पर किया जाता है, तो एक रिट याचिका दोनों स्थानों पर सुनवाई योग्य होगी। दूसरे शब्दों में, चूंकि अपीलीय प्राधिकारी का आदेश वाद हेतुक का हिस्सा बनता है, इसलिए एक रिट याचिका उस उच्च न्यायालय में सुनवाई योग्य होगी जिसके अधिकार क्षेत्र में यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्थित है कि अपीलीय प्राधिकारी का आदेश भी रद्द किये जाने योग्य है और मूल

प्राधिकारी का आदेश अपीलीय प्राधिकारी के साथ विलीन हो जाता है।"

8. कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड (सुप्रा) का इस न्यायालय ने मोसराफ हुसैन खान बनाम भागीरथा इंजीनियरिंग लिमिटेड और अन्य [(2006) 3 एससीसी 658] में अनुसरण किया गया है कि

"26. कुसुम इंगोट्स एंड अलॉयज लिमिटेड बनाम भारत संघ 14 में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट रूप से माना कि एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को दूसरे के मुकाबले निर्धारित करने की दृष्टि से रिट याचिका में दिए गए तथ्य इस आधार पर एक सांठगांठ होनी चाहिए कि प्रार्थना किस आधार पर की जा सकती है और जिन तथ्यों का इससे कोई लेना-देना नहीं है, वे अदालत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए वाद हेतुक नहीं बन सकते। उस मामले में यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि केवल इसलिए कि जिस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई कानून पारित किया गया है, उसका एकमात्र क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं होगा, बल्कि सभी उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा, जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है..."

9. ओम प्रकाश श्रीवास्तव बनाम भारत संघ और अन्य [(2006) 6 एससीसी 207] में, अभिनिर्धारित किया गया:-

12. अभिव्यक्ति " वाद हेतुक" ने न्यायिक रूप से तय अर्थ प्राप्त कर लिया है। प्रतिबंधित अर्थ में "वाद हेतुक" का अर्थ उन परिस्थितियों से है जो प्रतिक्रिया के अधिकार या तत्काल अवसर का उल्लंघन करती हैं। व्यापक अर्थ में, इसका मतलब मुकदमे के संधार्य के लिए आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें न केवल अधिकार का उल्लंघन शामिल है, बल्कि अधिकार के साथ जुड़ा उल्लंघन भी शामिल है। अनिवार्य रूप से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभिव्यक्ति का मतलब हर तथ्य है, जिसे अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, वादी के लिए साबित करना आवश्यक होगा। प्रत्येक तथ्य, जिसे साबित करना आवश्यक है, साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े से अलग, जो प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक है, "वाद हेतुक" में शामिल है। (देखें राजस्थान उच्च न्यायालय अधिवक्ता "संघ बनाम भारत संघ)"

10. उत्तरांचल फॉरेस्ट रेंजर्स एसो. (डायरेक्ट रिक्यूर्ट) और अन्य बनाम यूपी राज्य। और अन्य [(2006) 10 एससीसी 346], इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है:-

> "44. दूसरा आक्षेपित आदेश दिनांक 12-4-2004 है।
>
> निम्नलिखित कारणों से और अधिक दूषित हो गया:-

(ए) फोरम - दूसरी रिट याचिका में चुनौती के तहत वरिष्ठता सूची 2002 की उत्तरांचल राज्य सरकार की वरिष्ठता सूची थी और ऐसी चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष नहीं की जा सकती थी।

(बी) पक्ष- सीधे भर्ती किए गए किसी भी व्यक्ति को, जो आदेश से सीधे तौर पर प्रभावित होगा, रिट याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए उच्च न्यायालय को मामले में प्रतिस्पर्धी दलीलों का लाभ नहीं मिला। हालाँकि, उत्तरांचल राज्य के प्रमुख सचिव को एक पक्ष बनाया गया था, लेकिन उक्त पक्ष को कभी भी तामिल नहीं दी गई। एकमात्र प्रतिवादी जिसे सुना गया वह उत्तर प्रदेश राज्य था। जिसकी इस मामले में कोई हिस्सेदारी नहीं थी क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष सभी रिट याचिकाकर्ता उत्तरांचल राज्य के प्रासंगिक तिथि पर कर्मचारी थे, इसलिए यह स्पष्ट है कि रिट याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से संबंधित सामग्री को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था, इसी के अनुसार वर्तमान अपीलकर्ताओं को एसएलपी दायर करने के लिए इस न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ी।"

उक्त निर्देश इस प्रस्ताव के लिए प्राधिकारी हैं कि केवल उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा जिसके अंतर्गत, पूर्ण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ था। इस मामले में, वाद हेतुक का कोई भी हिस्सा कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ।

11. कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर वाद हेतुक झारखंड राज्य के भीतर मुगमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, हमारी राय है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता - कंपनी का मुख्य कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित थ। सिर्फ यह तथ्य कलकत्ता उच्च न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करेगा, खासकर जब प्रधान कार्यालय का प्रतिवादी के खिलाफ पारित सजा के आदेश से कोई लेना-देना नहीं था।

12. तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। कोई लागत अधिरोपित नहीं की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अश्लेषा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।